

“मुख्य समाचार”

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सड़कों, पुलों व रज्जुमार्ग परियोजनाओं को लेकर उदार वित्तीय सहायता देने का केन्द्र से किया आग्रह।
- राज्य सरकार ने हिमाचल में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार से मांगा सहयोग।
- उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा—शिमला में बनने वाले देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य 2025 से होगा शुरू।
- प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय टीम 3 जिलों मण्डी, कुल्लू और शिमला के दौरे पर।

मुख्यमंत्री—भेंट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में विभिन्न सड़कों, पुलों और रज्जुमार्ग परियोजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता और सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में चार नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला—मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्सों को चार लेन बनाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भी शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदेश को सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कांगड़ा जिला के देहरा में आरोग्य केंद्र व हेल्थ रिजॉर्ट और बिलासपुर जिला के औहर में एकीकृत पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री ने उचित स्तर पर एक माह के भीतर पर्यटन केंद्रों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं और इनकी शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ धनराशि जारी करने आश्वासन भी दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति

आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष एक बैठक के दौरान नीति आयोग से अन्य राज्यों की तुलना में आवश्यकताएं अलग होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलग मापदंड निर्धारित करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मामलों का अध्ययन करेगा।

उप-मुख्यमंत्री

शिमला में बनने वाले भारत के पहले सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य मार्च 2025 से शुरू होगा और इसके लिए एनडीबी ने अग्रिम टेंडर की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर बनने वाले इस रोपवे में 13 स्टेशन और 6 सौ 60 ट्रॉली होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इस रोपवे के निर्माण से शिमला शहर में लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केन्द्र सरकार भी प्रॉजेक्ट में पूर्ण मदद कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि दो चरणों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और पहला चरण इसी सरकार में पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि बिजली महादेव का रोपवे भी शुरू होने वाला है और बगलामुखी मंडी में रोपवे लगभग बनकर तैयार है जिसका सुरक्षा व तकनीकी पहलुओं का ट्रायल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं में हिस्सेदारी न देने के विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेलवे के दो प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के साथ बन रहे हैं।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान का दौरा किया। सक्षम बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी रहती है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि विशेष बच्चे सहयोग, मार्गदर्शन और अवसरों की वजह से जीवन के लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान का समर्पित अध्यापक वर्ग और अन्य स्टाफ बच्चों के सहयोग व उनके पोषण के लिए असाधारण कार्य कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने संस्थान के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की और सभी बच्चों को मिठाईयां भी वितरित कीं।

आपदा टीम

प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आठ सदस्यीय केंद्रीय टीम इन दिनों मण्डी, कुल्लू और शिमला जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव मिहिर कुमार के नेतृत्व में केन्द्रीय दल ने आज पहले दिन मंडी व कुल्लू जिलों के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दल के सदस्यों ने मण्डी जिले की चौहार घाटी स्थित राजबन और जिला मुख्यालय के समीप मट्ट व वमाणु गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया और राजबन में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। बाद में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में केन्द्रीय दल ने संबंधित विभागों व जिला प्रशासन से नुकसान के बारे में चर्चा कर ब्यौरा लिया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मण्डी जिले में इस वर्ष बरसात के कारण करीब 2 सौ 13 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने केन्द्रीय दल से नुकसान के बारे में उदारतापूर्वक विचार करते हुए हर सम्भव सहायता मदद प्रदान करने का आग्रह किया। इस बीच कुल्लू के नगवाई में उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने केन्द्रीय दल के सदस्यों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान की जानकारी प्रदान की। ये दल कल कुल्लू जिले के कसोल और मलाणा क्षेत्र का दौरा करने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।

कुलदीप पठानिया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में क्रीमिलेयर और आरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित दो दिवसीय युवा संसद का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शुभारम्भ किया। युवा संसद को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति विशेष, विचारधारा या संस्थान सर्वोच्च नहीं है बल्कि सिस्टम सर्वोच्च होता है। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी को समान अवसर देने की वकालत करते हुए सभी संस्थाओं को केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर अपनी योजनाएं निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस युवा संसद में क्रीमिलेयर और आरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर हिमाचल सहित अन्य राज्यों के करीब एक सौ 70 विद्यार्थी विस्तृत ढंग से अपने विचार रखेंगे।

विक्रमादित्य सिंह

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान आज कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये धनराशि प्रदेश के 8 सौ गांवों में बेहतर सड़क सम्पर्क सुनिश्चित बनाने पर खर्च की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के हितों को केन्द्र के समक्ष मजबूती से रख रही है और हाल ही में केन्द्र ने लोक निर्माण विभाग के लिए 3 सौ 50 करोड़

रूपए स्वीकृत किए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष करीब 3 हजार करोड़ रूपए का सहयोग केन्द्र से मिला था। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे अपने विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार और कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

चन्द्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में किसानों को खेतीबाड़ी से संबंधित तकनीकों के बारे जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर किसानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि की नई आधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने के लिए किसान मेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मेले में किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की गई और खेतों में सप्रे करने के लिए ड्रोन शो आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने जाईका परियोजना के 4, कृषि विभाग के 13 और आत्मा परियोजना के 7 प्रतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि के चैक वितरित किए।

गोविंद ठाकुर

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बिजली बोर्ड के इंजीनियरिंग के 51 पदों सहित 81 चालकों की सेवाओं को समाप्त करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को प्रदेश के निष्ठावान कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील कदम करार दिया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सुखू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था लेकिन मौजूदा हालात व्यवस्था पतन का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जिन गारंटियों के दम पर सत्ता में आई थी उनको पूरा करने के बजाए सुविधाएं छीनने में लगी हैं। गोविंद ठाकुर ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर तुरंत बहाल करने का सरकार से आग्रह किया है।

‘मुख्य समाचार एक बार फिर’

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सड़कों, पुलों व रज्जुमार्ग परियोजनाओं को लेकर उदार वित्तीय सहायता देने का केन्द्र से किया आग्रह।
- राज्य सरकार ने हिमाचल में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार से मांगा सहयोग।
- उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा—शिमला में बनने वाले देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य 2025 से होगा शुरू।
- प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय टीम 3 जिलों मण्डी, कुल्लू और शिमला के दौरे पर।